अनुदान संख्या 66 - संसदीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 66–MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4,04,00			
			5,76,00	4,52,48	–1,23,52
पूरक	Supplementary	1,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,21,80

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में कुल बचतें (123.52 लाख रु.) फरवरी 2004 में प्राप्त किए गए 172.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 72 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.123.52 lakhs) constituted 72 percent of the supplementary grant of Rs.172.00 lakhs obtained in February, 2004 and 21 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:–

			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat–General Services				
मू.	O.	404.00			
		172.00	454.20	452.48	–1.72
पु.	R.	–121.80			

(I) "सचिवालय - संसदीय कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत 404.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 172.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 576.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो घरेलू हवाई यात्रा में कमी आने, लोक सभा के जल्दी भंग हो जाने की वजह से एक संसदीय

(I) Under "Secretariat – Ministry of Parliamentary Affairs" – the original provision of Rs.404.00 lakhs was augmented to Rs.576.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.172.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.123.52 lakhs – due

प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने के प्रस्ताव का परित्याग करने, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम संख्या में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा किए जाने, विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं के समन्वयकों के लिए अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम जैसे कुछ आयोजनों/समारोहों का आयोजन न किए जाने के कारण 123.52 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

to decrease in domestic air journeys performed, abandonment of the proposal for sending one Parliamentary Delegation abroad owing to early dissolution of the Lok Sabha, visiting of lesser number of foreign delegations to India during the current financial year, non–holding of some events/functions like orientation course for the co-ordinators of National Youth Parliament Competitions for Universities/Colleges.